माननीय मंत्री (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) के लिए जैस, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी, 2008 को राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान की आधारशिला (Foundation) रखे जाने के समारोह के अवसर पर अभिभाषण।

आदरणीया श्रीमती सोनिया गांधी, यूपीए अध्यक्षा, मंत्रालय में मेरे सहकर्मी श्री दिनशा पटेल, श्री राहुल गांधी, संसद सदस्य, श्री सतीश शर्मा, संसद सदस्य, श्री एम.एस.श्रीनिवासन, सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, RGIPT सोसाइटी के अध्यक्ष, प्रेस और इलैक्ट्रानिक संचार माध्यमों से आए मित्रगण, प्रिय बच्चों, देवियों और सज्जनो।

2. राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (RGIPT) की आधारशिला (Foundation) रखे जाने के इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित होने में मुझे विशेष गर्व का अनुभव हो रहा है। मैं, हमारे कल्पना शक्ति के धनी नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नाम पर नामकरण किए जा रहे इस "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान" की आधारशिला (Foundation) रखे जाने के लिए सहमत हुई श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। वास्तव में यह देश के पेट्रोलियम क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना है।

3. भारत ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा उपभोक्ता है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्याधीन विकास (Targeted

Growth) को सहायता प्रदान करने के लिए हमारी ऊर्जा जरूरतें अगले पांच वर्ष में 40% बढ़ जाने का अनुमान है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने अपने विजन 2025, नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (NELP) और योजना आयोग की एकीकृत ऊर्जा नीति (Integrated Energy Policy) के जरिए अन्वेषण और उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक पहल कीं हैं। यह अनुगामी NELP कार्यक्रमों में अपेक्षाकृत अधिक स्टेक (Stakes) के साथ निजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारतीय बेसिनों के अन्वेषण में बढ़ती रूचि से स्पष्ट है। इस उद्योग को परिवर्तन के प्रति लगातार प्रतिक्रिया दिखानी है - यह एक ऐसा उद्योग है जिसे प्रबंधकीय, तकनीकी, आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक अनेक प्रकार की चुनौतियों से निपटने की क्षमता रखने वाले सर्वाधिक प्रतिभाशाली स्नातकों को आकर्षित, विकसित करना है तथा उन्हें अपने साथ बनाए रखना है।

4. पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र में जनशक्ति की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आईआईटी (IITs) के अनुरूप संसद के एक अधिनियम (Act) द्वारा "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान" के रूप में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (RGIPT) की स्थापना की शुरूआत की है। संस्थान को सार्वजनिक क्षेत्र के छः तेल उपक्रमों तथा तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) द्वारा समर्थन दिया गया है और इसे "कार्पोरेट यूनिवर्सिटी" (Corporate University) कहा जा सकता है,

यह अपनी किस्म का पहला विश्वविधालय है जिसे उद्योग के सक्रिय भागीदारी से स्थापित किया गया है। देश में पेट्रोलियम क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है और इस संस्थान की स्थापना के द्वारा प्रशिक्षित जनशक्ति (Trained Manpower) की मांग को पूरा करने के लिए इसकी शुरूआत की गई है।

5. संस्थान का प्रमुख उद्देश्य निकट भविष्य में विश्व स्तरीय शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पेट्रोलियम और ऊर्जा उद्योग के लिए अनुसंधान उपलब्ध कराना है। संस्थान ने अन्य देशों में इसी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों (Educational Institutes) के साथ संपर्क स्थापित किए हैं और उत्तम स्तर के अवसर को बढ़ावा दिया है। संपूर्ण पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र के लिए भारत को एक ग्लोबल जनशक्ति केन्द्र बनाना इस संस्थान का उद्देश्य है।

6. संस्थान की स्थापना राय बरेली जिले के "**जैस**" में की जा रही है। संस्थान ने पहले ही लगभग 47.8 एकड़ भूमि की खरीद कर ली है, जहां आज हम आधारशिला स्थापना समारोह मना रहे हैं। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 695.58 करोड़ रुपए है, जिसमें से 435 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) और 260.58 करोड़ रुपए आवर्ती व्यय (Recurring Expenditure) के लिए रखे गये हैं। सरकार ने पूंजीगत व्यय के एक भाग के पूर्ति के लिए 285 करोड़

रुपए बजटीय सहायता से प्रदान किए हैं और शेष 150 करोड़ रुपए तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) द्वारा वहन किए जाएंगे।

7. RGIPT इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, अनुसंधान आदि क्षेत्रों में पेट्रोलियम और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का प्रशिक्षण देंगे। शैक्षणिक वर्ष 2008-2009 से चरणबद्ध रूप से स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्रियों, पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, डाक्टरेट (Doctoral) से जुड़े कार्यक्रमों को शुरू करने का प्रस्ताव है। संस्थान का अपना कैम्पस उत्तर प्रदेश में जिला राय बरेली के **जैस** में होगा। आरंभ में पाठ्यक्रमों की शुरूआत अस्थायी कैम्पस में की जाएगी।

8. मैं एक बार फिर से श्रीमती सोनिया जी और श्री राहुल गांधी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने इस अवसर की शोभा बढ़ाई और आशा करता हूं कि इस कदम से न केवल हमारे युवा वर्ग को विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा बल्कि रोजगार देने, सहायक इकाईयों को अपनी स्थापना करने में और ऐसी कई संस्थाओं को इस संस्थान की स्थापना से लाभान्वित होने के अवसर उपलब्ध होंगे।

धन्यवाद,

जय हिन्द,

माननीय मंत्री (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) के लिए जैस, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी,2008 को राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान की आधारशिला रखे जाने के समारोह के अवसर पर अभिभाषण।

आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, यूपीए अध्यक्षा, मंत्रालय में मेरे सहकर्मी श्री दिनशा पटेल, श्री राहुल गांधी, संसद सदस्य, श्री सतीश शर्मा, संसद सदस्य, श्री एम.एस.श्रीनिवासन, सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,

अध्यक्ष, आरजीआईपीटी सोसाइटी, प्रेस और इलैक्ट्रानिक संचार माध्यमों से आए मित्रगण, प्रिय बच्चों, देवियों और सज्जनो।

2. राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) की आधारशिला रखे जाने के इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित होने में मुझे विशेष गर्व का अनुभव हो रहा है। मैं, हमारे कल्पना शक्ति के धनी नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नाम पर नामकरण किए जा रहे इस "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान " की आधारशिला रखे जाने के लिए सहमत हुई श्रीमती सोनिया गांधी के प्रति आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। वास्तव में यह देश के पेट्रोलियम क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना है।

3. भारत ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा उपभोक्ता है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्याधीन विकास को सहायता प्रदान करने के लिए हमारी ऊर्जा जरूरतें अगले पांच वर्ष में 40% बढ़ जाने का अनुमान है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने अपने विजन 2025, नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) और योजना आयोग की एकीकृत ऊर्जा नीति के जरिए यथा अभिदर्शित अन्वेषण और उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक पहलकदमियां कीं हैं। यह अनुगामी एनईएलपी कार्यक्रमों में अपेक्षाकृत अधिक पण के साथ निजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारतीय बेसिनों के अन्वेषण में बढ़ती रूचि से स्पष्ट है। इस उद्योग को परिवर्तन के प्रति लगातार प्रतिक्रिया

दिखानी है - यह एक ऐसा उद्योग है जिसे प्रबंधकीय, तकनीकी, आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक अनेक प्रकार की चुनौतियों से निपटने की क्षमता रखने वाले सर्वाधिक प्रतिभाशाली स्नातकों को आकर्षित, विकसित करना है तथा उन्हें अपने साथ बनाए रखना है।

4. पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र में जनशक्ति की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आईआईटी के अनुरूप संसद के एक अधिनियम द्वारा "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान " के रूप में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) की स्थापना की शुरूआत की है। संस्थान को सार्वजनिक क्षेत्र के छः तेल उपक्रमों तथा ओआईडीबी (तेल उद्योग विकास बोर्ड) द्वारा समर्थन दिया गया है और इसे "कार्पोरेट यूनिवर्सिटी " कहा जा सकता है, यह अपनी किस्म का पहला विश्वविधालय है जिसे उद्योग के सक्रिय भागीदारी से स्थापित किया गया है। देश में पेट्रोलियम क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है और प्रशिक्षित जनशक्ति के लिए इसकी मांग को पूरा करने के लिए, स्वयं क्षेत्र की ओर से यह शुरूआत की गई है।

5. संस्थान का प्रमुख उद्देश्य निकट भविष्य में विश्व स्तरीय शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पेट्रोलियम और ऊर्जा उद्योग के लिए अनुसंधान उपलब्ध कराना है। संस्थान ने अन्य देशों में इसी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों के साथ संपर्क स्थापित किए हैं और उत्तम स्तर के शैक्षणिक और सीखने

के अवसर को बढ़ावा दिया है। संस्थान की ऐसी आकांक्षा है कि संपूर्ण पेट्रोलियम और ऊर्जा स्पेक्ट्रम के लिए भारत को एक वैश्विक जनशक्ति केन्द्र बनाया जाए।

6. संस्थान की स्थापना राय बरेली जिले के **"जैस"** में की जा रही है। संस्थान ने पहले ही लगभग 47.8 एकड़ भूमि की खरीद कर ली है, जहां आज हम आधारशिला स्थापना समारोह मना रहे हैं। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 695.58 करोड़ रुपए है, जिसमें से 435 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय और 260.58 करोड़ रुपए आवर्ती व्यय के लिए रखे गये हैं। सरकार ने पूंजीगत व्यय के एक भाग के पूर्ति के लिए 285 करोड़ रुपए बजटीय सहायता से प्रदान किए हैं और शेष 150 करोड़ रुपए तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) द्वारा वहन किए जाएंगे।

7. आरजीआईपीटी इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, अनुसंधान आदि क्षेत्रों में पेट्रोलियम और नवीकरणीय ऊर्जा की दोनों क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का प्रशिक्षण देंगे। शैक्षणिक वर्ष 2008-2009 से चरणबद्ध रूप से स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्रियों, पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, डाक्टरेट से जुड़े कार्यक्रमों को शुरू करने का प्रस्ताव है। संस्थान का अपना कैम्पस उत्तर प्रदेश में जिला राय बरेली के **जैस** में होगा। आरंभ में पाठ्यक्रमों की शुरूआत अस्थायी कैम्पस में की जाएगी।

8. मैं एक बार फिर से श्रीमती सोनिया जी और श्री राहुल गांधी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने इस अवसर की शोभा बढ़ाई और

आशा करता हूं कि इस कदम से न केवल हमारे युवा वर्ग को विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा बल्कि रोजगार सृजन, सहायक इकाईयों को अपनी स्थापना करने में और ऐसी कई संस्थाओं को इस संस्थान की स्थापना से लाभान्वित होने के अवसर उपलब्ध होंगे।

धन्यवाद,

जय हिन्द,

माननीय मंत्री (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) के लिए जैस, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी, 2008 को राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान की आधारशिला (Foundation) रखे जाने के समारोह के अवसर पर अभिभाषण।

आदरणीया श्रीमती सोनिया गांधी, यूपीए अध्यक्षा, मंत्रालय में मेरे सहकर्मी श्री दिनशा पटेल, श्री राहुल गांधी, संसद सदस्य, श्री सतीश शर्मा, संसद सदस्य, श्री एम.एस.श्रीनिवासन, सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, RGIPT सोसाइटी के अध्यक्ष, प्रेस और इलैक्ट्रानिक संचार माध्यमों से आए मित्रगण, प्रिय बच्चों, देवियों और सज्जनो।

2. राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (RGIPT) की आधारशिला (Foundation) रखे जाने के इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित होने में मुझे विशेष गर्व का अनुभव हो रहा है। मैं, हमारे कल्पना शक्ति के धनी नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नाम पर नामकरण किए जा रहे इस "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान " की आधारशिला (Foundation) रखे जाने के लिए सहमत हुई श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। वास्तव में यह देश के पेट्रोलियम क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना है।

3. भारत ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा उपभोक्ता है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्याधीन विकास (Targeted Growth) को सहायता प्रदान करने के लिए हमारी ऊर्जा जरूरतें अगले पांच वर्ष में 40% बढ़ जाने का अनुमान है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने अपने विजन 2025, नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (NELP) और योजना आयोग की एकीकृत ऊर्जा नीति (Integrated Energy Policy) के जरिए अन्वेषण और उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक पहल कीं हैं। यह अनुगामी NELP कार्यक्रमों में अपेक्षाकृत अधिक स्टेक (Stakes) के साथ निजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारतीय बेसिनों के अन्वेषण में बढ़ती रूचि से स्पष्ट है। इस उद्योग को परिवर्तन के प्रति लगातार प्रतिक्रिया दिखानी है - यह एक ऐसा उद्योग है जिसे प्रबंधकीय, तकनीकी, आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक अनेक प्रकार की चुनौतियों से निपटने की क्षमता रखने वाले सर्वाधिक प्रतिभाशाली स्नातकों को आकर्षित, विकसित करना है तथा उन्हें अपने साथ बनाए रखना है।

4. पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र में जनशक्ति की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आईआईटी (IITs) के अनुरूप संसद के एक अधिनियम (Act) द्वारा "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान" के रूप में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (RGIPT) की स्थापना की शुरूआत की है। संस्थान को सार्वजनिक क्षेत्र के छः तेल उपक्रमों तथा तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) द्वारा समर्थन दिया गया है और इसे "कार्पोरेट यूनिवर्सिटी " (Corporate University) कहा जा सकता है, यह अपनी किस्म का पहला विश्वविधालय है जिसे उद्योग के सक्रिय भागीदारी से स्थापित किया गया है। देश में पेट्रोलियम क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है और इस

संस्थान की स्थापना के द्वारा प्रशिक्षित जनशक्ति (Trained Manpower) की मांग को पूरा करने के लिए इसकी शुरूआत की गई है।

5. संस्थान का प्रमुख उद्देश्य निकट भविष्य में विश्व स्तरीय शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पेट्रोलियम और ऊर्जा उद्योग के लिए अनुसंधान उपलब्ध कराना है। संस्थान ने अन्य देशों में इसी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों (Educational Institutes) के साथ संपर्क स्थापित किए हैं और उत्तम स्तर के अवसर को बढ़ावा दिया है। संपूर्ण पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र के लिए भारत को एक ग्लोबल जनशक्ति केन्द्र बनाना इस संस्थान का उद्देश्य है।

6. संस्थान की स्थापना राय बरेली जिले के "**जैस**" में की जा रही है। संस्थान ने पहले ही लगभग 47.8 एकड़ भूमि की खरीद कर ली है, जहां आज हम आधारशिला स्थापना समारोह मना रहे हैं। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 695.58 करोड़ रुपए है, जिसमें से 435 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) और 260.58 करोड़ रुपए आवर्ती व्यय (Recurring Expenditure) के लिए रखे गये हैं। सरकार ने पूंजीगत व्यय के एक भाग के पूर्ति के लिए 285 करोड़ रुपए बजटीय सहायता से प्रदान किए हैं और शेष 150 करोड़ रुपए तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) द्वारा वहन किए जाएंगे।

7. RGIPT इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, अनुसंधान आदि क्षेत्रों में पेट्रोलियम और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का प्रशिक्षण देंगे। शैक्षणिक वर्ष 2008-2009 से चरणबद्ध रूप से स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्रियों, पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, डाक्टरेट (Doctoral) से जुड़े कार्यक्रमों को शुरू करने का प्रस्ताव है। संस्थान का अपना कैम्पस उत्तर प्रदेश में जिला राय बरेली के **जैस** में होगा। आरंभ में पाठ्यक्रमों की शुरूआत अस्थायी कैम्पस में की जाएगी।

8. मैं एक बार फिर से श्रीमती सोनिया जी और श्री राहुल गांधी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने इस अवसर की शोभा बढ़ाई और आशा करता हूं कि इस कदम से न केवल हमारे युवा वर्ग को विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा बल्कि रोजगार देने, सहायक इकाईयों को अपनी स्थापना करने में और ऐसी कई संस्थाओं को इस संस्थान की स्थापना से लाभान्वित होने के अवसर उपलब्ध होंगे।

धन्यवाद,
जय हिन्द,

राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने और इसे "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान" घोषित करने की जरूरत।

वर्ष 1999 में नई अन्वेषण लाइसेंस नीति आरंभ हुई जिसे उत्तरोत्तर और अधिक आकर्षक बनाया गया है। इस नीति से विदेशी कंपनियों और भारतीय निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में भारत में अन्वेषण रकबों के अर्जन के लिए अत्यधिक उत्साह उत्पन्न हुआ है। आज की तारीख तक भारत में केवल 30% तलछटीय बेसिनों का अन्वेषण किया गया है। वर्ष 2015 तक अन्वेषण कवरेज को बढ़ाकर 100% तक ले जाने की योजना है। इस संदर्भ में प्रौद्योगिकी के अलावा आने वाले वर्षों में पर्याप्त संख्या में योग्यता प्राप्त कार्मिकों की उपलब्धता की आवश्यकता पड़ेगी।

महोदय, पेट्रोफेड के लिए परामर्शक प्राइसवाटर हाऊस कूपर्स द्वारा आयोजित हालिया अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि भारत में पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता और जरूरत के बीच अंतर वर्ष 2019 तक लगभग 36000 हो जाएगा। पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा जैस, उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।

यह संस्थान पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भविष्य के अग्रणियों और नवाचारकों के रूप में सेवा करने के लिए सक्षम विश्व श्रेणी के तकनीकी मानव संसाधनों को तैयार करने के लिए स्रोत शीर्ष के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। आरंभ में यह संस्थान एक किराए के परिसर से शैक्षणिक वर्ष 2008-09 से बेसिक अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को प्रवेश देकर अपने शैक्षणिक प्रचालन आरंभ करेगा। पूर्णतः प्रचालनरत हो जाने पर इस संस्थान में 7 बी.टेक, 6 एकीकृत निष्णात उपाधियां, 8 एमटेक/एमबीए और 12 पीजीडी और पीएचडी कार्यक्रम होंगे।

परियोजना की कुल अनुमानित पूंजीगत लागत 435 करोड़ रुपए है, जिसे अंशतः 285 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता तथा 150 करोड़ रुपए की तेल उद्योग विकास बोर्ड सहायता से पूरा किया जाएगा। 260.58 करोड़ रुपए के कुल अनुमानित आवर्ती व्यय को

250.00 करोड़ रुपए की स्थायी निधि पर मिलने वाले ब्याज से पूरा किया जाएगा, और इसकी प्राप्ति सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों, विद्यार्थी शुल्कों, दान तथा संस्थान के अन्य उपार्जनों के अंशदान से प्राप्त की जाएगी। ऐसी परिकल्पना है कि वर्ष 2015-16 तक संस्थान आत्म-निर्भर हो जाएगा।

यह प्रस्तावित है कि संस्थान को उसके शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय कार्य प्रणाली के अनुसार स्वायतत्ता का उच्च दर्जा प्राप्त है। यह उसके अपने अधिकार में उसे विधिक शक्तिप्रदत्त बनाएगा ताकि उपाधियां तथा अन्य शैक्षणिक विशेषताओं तथा अधिकार प्रदान करने में वह सक्षम हो सकें। इसके अतिरिक्त, यह परिकल्पना की गई है कि संस्थान को भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का संरक्षण और समर्थन प्राप्त होगा। यह राष्ट्र के हित में है कि सरकार ने संस्थान को विकास के उसके प्रारंभिक और निर्णायक स्तर पर सहारा दिया है ताकि संस्थान बिना किसी समझौते के अपने कार्यक्रमों की शुरूआत कर सके और उन्हें चला सके तथा उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों की शुरूआत के समय विश्व-स्तरीय बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान " का दर्जा न मिलने की स्थिति में, प्रतिष्ठित फैकल्टी सदस्यों तथा योग्य विद्यार्थियों को आकृष्ट कर पाना संभव नहीं होगा।

संस्थान की ऊपर बताई गई स्थापना की प्रस्तावित विधि को ध्यान में रखते हुए, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान को संसद के एक ऐसे अधिनियम द्वारा "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान" के रूप में निगमित किया गया है, जिसे अभिशासित संरचना के साथ-साथ विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह संस्थान को वही स्तर और दर्जा प्रदान करे जो आईआईटी को प्राप्त है।

*****